आयात नहीं करेंगे और उन सामानों को प्राइवेट सैक्टर में बनाने की इजाजत नहीं देंगे। क्या आप इसका आश्वासन सदन के अन्दर देंगी, जबकि प्रधान मंत्री यहां मौजूद है ?

KUMARI ABHA MAITI: That is the policy of the present Government.

SHRI VIREN J. SHAH: In view of the earlier reply about losses year after year incurred by this Corporation and certain difficulties which lead to higher cost of production, would the honourable Minister enlighten us whether, in the timing of conceiving of this particular project and implementing it, in the type of equipment that is set up, in all these things there is any basic defect which makes it difficult for this particular Corporation to function in an efficient manner?

KUMARI ABHA MAITI: There is no difficulty in it.

SHRIMATI AMBIKA SONI: Is it or is it not a fact that the panel set up by the Ministry of Industry has said in its various recommendations that there is a lack of rapport between the manufacturers and the users of mining equipment and that is the reason why the public sector MAMC is suffering losses? It is also suggested that when the Government undertakes import of certain equipment which may not be made in the country at the moment, it should combine it with the simultaneous transfer of technology to our manufacturing unit. Is it or is it not a fact that the Government has overlooked this suggestion along with the suggestion of having a development funds to modernise the manufacturing units of our country?

KUMARI ABHA MAITI: The Government is helping MAMC to modernise the whole thing and also for diversification. It is not correct to say that there is no rapport between MAMC and the other units.

Loveraj Kumar Committee report on the cement industry

*242. SHRI AMARPROSAD CHAKRABORTY: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Loveraj Kumar Committee on the cement industry has submitted its report to Government; and

(b) if so, what are the main recommendations of the Committee and whether Government have decided to implement the recommendations?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) रिपोर्ट की जांच की जा रही है और जब तक सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर निर्णय नहीं ले लिया जाता है, समिति द्वारा की गई सिफारिशों को प्रकट करना लोकहित में नहीं है।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Yes, Sir.

(b) The report is under examination and it is not in the public interest to disclose the recommendations made by the Committee until decisions are taken by the Government on these recommendations.

SHRI AMARPROSAD CHAKRABORTY: Sir, this is another problem touching the people of the entire country. Cement is exported to the tune of 6.30 lakh tonnes to the neighbouring countries of Bangladesh, Pakistan and Sri Lanka and 8.4 lakh tonnes of cement is being imported from Korea, Romania and Poland. The people of this country are not getting their normal requirement of cement. And the price of cement has risen from Rs. 344 to Rs. 666 in the market. The Loveraj Kumar Committee has recommended in its report that addi-

†[ ] English translation.

tional incentives should be given. So I would like to know what steps the Government has taken so far to reach cement to the people of this country instead of exporting it to outside countries and without meeting the requirements of the people of India.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : श्रीमन्, आपकी आज्ञा हो तो मै जवाब दे सकता हू यद्यपि मूल प्रश्न दूसरा है, वह रिपोर्ट के बारे में है और उस से यह सवाल उठता नहीं है। लेकिन इस प्रश्न का सार्वजनिक महत्व है इसलिए मैं थोड़ा जवाब देना चाहूंगा।

जहां तक एक्सपोर्ट की बात है, सिर्फ भूटान, बंगलादेश, नेपाल जैसे नेबरिंग और अंडर डेवलप्ड देशों को छोड कर, जिन को हमारी मदद की ज़रूरत है, और कहीं एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। दूसरे, जहां तक हमारी कमी है, इस कमी को पूरा करने के लिए हमने 1978–79 में 27 मिलियन टन्स की क्षमता (केपेसिटी) बढ़ायी है और उसका प्रोडक्शन 40 पर सेन्ट तक आ गया है।

श्रीमन्, जहां तक एडिशनल कैपेसिटी बढ़ाने की बात है जिससे हम अपनी आवश्यकता पूरी कर सकें उसके लिए लार्ज स्केल मे 22 मिलियन टन्स की कैपेसिटी बढाने की क्षमता हमने प्राप्त कर ली है और मिनी क्षेत्र मे 10 लाख टन के लगभग क्षमता हमने बढायी है और जो एडिशनल कपेसिटी है वह 1978-79 में 1.13 मिलियन टन्स की कैपेसिटी में पूरा करने का प्रयास है ताकि क्षमता को ज्यादा बढ़ाये और जो कमी है उसको पूरा करें। जिस गति से कमी चल रही है उसी गति से हम उस को पूरा करने मे आगे आने वाले समय में सक्षम हो जाएंगे।

MR. CHAIRMAN: Are you going to ask about this particular committee's report?

SHRI AMARPROSAD CHAKRABORTY: Yes. They are avoiding the main thing. Cement is being sold to our own people in the black-market where the price is Rs. 660. The Loveraj Kumar Committee's Report was submitted to the Government in January and they have suggested something on which he is silent. Is it a fact that the Committee has recommended an increase of Rs. 39.90 per tonne at the retail level over the existing price? Is it also a fact that the Loveraj Committee has recommended that instead of Rs. 344 an amount of Rs. 225 should be charged after the return of the income tax? Sir, he is keeping us in the dark. People in this country are not getting cement and they are forced to buy cement at Rs. 660/66 in the black market. He is not giving us the report. But I am reading from it...

MR. CHAIRMAN: He has replied that the report is under consideration.

SHRI AMARPROSAD CHAKRABORTY: But people of India are not getting cement. I want to know what steps he is taking to ensure proper supply of cement. He has given a vague answer. They are sending cement to other countries.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : श्रीमन्, मैंने पहले ही बताया कि एक्सपोर्ट में भी भूटान और नेपाल को छोड़कर दूसरे देशों को बन्द कर दिया गया है। जहां तक रिपोर्ट की बात है मैने पहले बताया कि वह अन्डर कंसीडरेशन है। इसके टर्म्स और रिफरेंस मैं बता सकता हूं लेकिन जब तक फाइनल कंसीडरेशन नहीं निकलता है तब तक मैं इसके बारे में बताने मे असमर्थ हूं।

श्री प्रकाश महरोत्रा : मान्यवर, इस देश में सीमेंट न मिल रहा है और न सीमेंट पर मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ये जो रिकमेंडेशन्स है उसमे क्या मिनी सीमेंट प्लांट्स के बारे में रिकमेंडेशन

है और दूसरी बात यह है कि मिनी सीमेंट प्लांट इस देश में ज्यादा से ज्यादा लगें इसके लिए सरकार क्या सहूलियतें देना चाहती है?

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : चौथा सवाल भी मिनी प्लांट का है इसलिए मैं चाहता हूं कि उसको भी साथ साथ ले लें ;

(Interruptions)

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : इसमें आगे सवाल है। यह जो आप पूछ रहे हैं . . .

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I have myself said that the recommendations are under their consideration.

SHRI ANANT PRASAD SHARMA: क्या मंत्री महोदय का ध्यान श्री जैन के इस वक्तव्य की तरफ गया है कि सन् 1976 और 1977 तक सीमेंट के उत्पादन की स्थिति ठीक थी। अब वह 1978 से गड़बड़ होनी आरम्भ हुई है। दूसरी तरफ एक सिफारिश यह है कि :

The Working Group which was constituted in April 1978 to ensure rapid development of the stagnated cement industry has strongly recommended that the system of control by way of licensing for he setting up of cement units should be withdrawn forthwith and this itself will go a long way in attracting further investments in setting up cement plants.

यह जो सिफारिश है, मैं पर्टीकुलर सिफारिश की बात नहीं कह रहा हूं, इसका क्या वह कार्यान्वियन करेंगे ? फिर एक तरफ जब सीमेंट बाहर से मंगाने की बात हो रही है तो दूसरी तरफ क्या उनको मालूम है कि डालमियां दादरी जो सीमेंट की फैक्टरी है उसके लिए मैनेजमेंट ने क्लोजर का नोटिस दिया है। क्या इसकी तरफ मंत्री जी कुछ ध्यान देंगे या करेंगे ?

MR. CHAIRMAN: This pertains to the Kumar Committee Report.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : इसका एक जवाब मैं दे देता हूं। उन्होंने कहा कि 1976–77 में प्रोडक्शन अधिक था और अब प्रोडक्शन गिर गया है। मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं कि 1976-77 में 21.63 मिलियन टन की कैपेसिटी थी और प्रोडक्शन 18.84 मिलियन टन था, 1977-78 में 21.87 मिलियन टन कैपेसिटी थी और 19.28 मिलियन टन प्रोडक्शन था। अर्थात् 1976–77 में लगभग 87 परसेंट कैपेसिटी का उत्पादन हुआ। इस साल कैपेसिटी 23 मिलियन टन है। और प्रोडक्शन अब तक, क्योंकि तीन महीने की रिपोर्ट बाकी है, 19.60 मिलियन टन है। अर्थात् 91 परसेंट प्रोडक्शन है और इसलिए यह स्थिति अच्छी है। जो रिकमेंडेशन आयी हैं उन पर केयरफुली इक्जामिन किया जा रहा है और 31 मार्च तक इसका फैसला कर लिया जायगा।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : डालमिया दादरी जो बन्द किया जा रहा है, जिसको नोटिस दी गयी है, इसके संबंध में जरा बताइये।

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Are you going to put your supplementary, Mr. Mallick?

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: Sir, let the honourable Minister of Industry and the Minister of State in that Ministry must remember that the previous Government was voted out of office because of its wrong policies with regard to import and export and they must see that, that policy is not being followed now. If it is followed, it should be corrected and the past mistakes should be rectified. I would also request them to check up and see that their officers who have to carry out the Governments policy do not carry with them the past legacy.

SHRI ANANT PRASAD SHARMA: What is the question, Sir.

MR. CHAIRMAN: Where is no question at all in this.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : श्रीमन्, इस प्रश्न के संदर्भ में तो यह प्रश्न नहीं है ।

MR. CHAIRMAN: Then why are you replying?

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : लेकिन जो लीगेसी मिली है वह सब के साथ है । मैंने तो सदस्यों को बताया है कि सीमेंट की जो कमी है उस के लिये हम ने क्या क्या कदम उठाये हैं और क्या क्या काम कर रहे है ।

श्री कल्प नाथ राय : क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आज देश में सीमेंट का इतना अभाव हो गया है कि 40 और 50 रूपये बोरी भी सीमेंट नहीं मिल रही है और यदि कोई ब्लैक मार्केट मे उस को लेना चाहता है तो उस को ट्रक या दो ट्रक भी आसानी से मिल सकती है । तो क्या माननीय मंत्री जो बतायेंगे और प्रधान मंत्री जी भी यहां मौजूद हैं, वह जानते है कि पूरे देश के पैमाने पर यह सीमेंट का संकट है । आज सीमेंट 40 या 50 रुपये बोरी मिल पाती है ब्लैक मार्केट मे, लेकिन वह सरकारी एजेंसियों के माध्यम से नहीं मिल रही है । तो यह समस्या, जो पूरें देश की समस्या बन गयी है, उस को हल करने के लिये वह कोई उपाय करेंगे ?

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : जहां तक सीमेंट की आवश्यकता का सवाल है वह हमारे देश के लिये 24 मिलियन टन की है और हमारा प्रोडक्शन 20 मिलियन टन के ऊपर है । हमारे पास 4 मिलियन टन सीमेंट की कमी है जिसमे से 2 मिलियन टन हम इंपोर्ट कर लेते है और बाकी दो मिलियन टन जो हम ने विभिन्न स्टेप्स लिये हैं, उन के द्वारा इस कमी को पूरा किया जायगा ।

श्री राम लखन प्रसाद गुप्त : माननीय मंत्री जी जिस क्षेत्र से आते हैं, मुंगेर जिले से, वहां के पास बकाई क्षेत्र मे बहुत बड़ा लाइम का डिपाजिट निकला है और उसके लिये बताया गया है कि वहां पर सीमेंट फैक्टरी बरसो तक चल सकती है । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की कोई योजना है कि जहां इस तरह के नये डिपाजिट हो और खास कर मुंगेर में जो निकला है आपके क्षेत्र में, वहां पर कोई कारखाना मंत्री जी स्थापित कराना चाहते है ?

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : श्रीमन्, जहां डिपाजिट्स मिले हैं उन क्षेत्रों को आइडेंटिफाई किया गया है और उन विभिन्न सरकारों को जिन के यहां यह साइट्स है उसकी जानकारी दे दी गयी है कि वहां यदि उन साइट्स को वह डवलप करना चाहते है तो उस के लिये योजना बना सकते हैं । जो कुछ हम किसी साइट के लिये करना चाहते हैं उस की जानकारी हम उन को देते रहते है ।

श्री सीताराम केसरी : सभापति जी, मै फिर कष्ट के साथ कहता हूं कि मंत्री महोदय के यहां न रहने का, उन की अनुपस्थिति का मुझे बड़ा दुख है, कारण यह है कि हिन्दुस्तान लीवर एक मल्टी नेशनल कंपनी ही नहीं है, वह एक ट्रांस मल्टी नेशनल कम्पनी है और उसने हमारे मिनिस्टर साहब, जार्ज फर्नेन्डीज साहब को साउन्ड किया है क्या यह सच है कि उसने उन को साउन्ड किया है, जार्ज फर्नेन्डीज साहब को कि वह दो हजार टन प्रोडक्शन करने की सीमेंट की फैक्टरी लगवाये और क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान लीवर को यह फैक्टरी उन्होंने देने का फैसला किया है ?

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : यह पर्सनल जानकारी की बात है । यह तो मिनिस्टर साहब ही बता सकते है कि उन को साउन्ड किया गया है या नही ।

श्री सीताराम केसरी : यह पर्सनल जानकारी की बात नही है । मैं चैलेंज करता हू कि यह गवर्नमेंट की बात है, पर्सनल नहीं है ।

I will read it out Sir. (*Interruptions*). Let me read it out.

MR. CHAIRMAN: Don't read out anything now.

SHRI SITARAM KESRI: I will read out, Sir. It says that they are explaining, the possibility. ... (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: Don't read anything now.

(*Interruptions*).

श्री सीताराम केसरी : आप मिनिस्टर की नाक है क्या । जार्ज फर्नेन्डीज के डिफेक्टो मिनिस्टर यहां पर बैठे हुए है । आप क्यों आगे बढ़ रहे है। (*Interruptions*) वह तो यहा बैठे हुए है । यह मल्टी नेशनल की बात है और आप राष्ट्रीयकरण की बात करते है और ट्रांस मल्टी नेशनल को यहां लाना चाहते हैं । आप टाटा और बिड़ला तथा दूसरी कंपनियों के राष्ट्रीयकरण की बात करते है ।

(*Interruptions*)

Incentives to scientists and research scholars for finding out-substitute for uranium

*243. SHRI KALRAJ MISHRA:
SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR:†
SHRI HARI SHANKAR BHABHRA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have given any incentives to scientists and research scholars to find out a substitute for uranium; and

(b) if so, what steps Government have taken in this regard?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) and (b) This is a part of the overall normal research and development effort. The question of giving any incentive to our scientists does not arise.

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Jagdish Prasad Mathur.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : इन्वेस्टमेन्ट के लिये केवल आर्थिक सहायता ही काफी नहीं है उनको विशेष साधन और प्रोत्साहन मिलने चाहिये । दो प्रश्न उठते है कि क्या यूरेनियम जो देश मे है उसकी खोज या दूसरी चीज जैसे प्लाटोनियम इसकी खोज हमारे यहा हो रही है या नही और दूसरे यह कि जो रिप्रोसेसिंग का प्लांट हमारा तारापुर मे है उस तारापुर के प्लांट को हमने क्यों तीन-चार साल से बन्द किया हुआ है । मेरी जानकारी गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है वह यह कि अमेरिका ने इस पर आपत्ति की थी इसलिये हमने रिप्रोसेसिंग प्लांट बन्द किया । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारे साइंटिस्ट को यह अवसर किया जायगा । रिप्रोसेसिंग के विषय मे कि वह वहीं पर प्लांट को चालू करें अथवा वहां से अन्यत्र कहीं और प्लांट हटा कर अपने इस प्रोसेस को आगे बढा कर वैज्ञानिक दृष्टि से खोज करे ?

श्री मोरारजी देसाई : साइंटिस्ट को जितनी सहूलियत चाहिये उतनी दी जा रही है जिससे वे अपना काम ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा सकें । जहां तक तारापुर के प्लूटोनियम की रिप्रोसेसिंग का सवाल है उसका जब तक एग्रीमेंट चालू है तब तक उसको हम नहीं कर सकते ।

श्री हरी शंकर भाभड़ा : सभापति महोदय प्रधान मंत्री जी ने इस सदन में भी और उस सदन में भी बार-बार इस बात की घोषणा की है कि यदि अमेरिका ने हम को यूरेनियम एग्रीमेंट के अन्तर्गत सप्लाई नही की तो हम उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे । मै प्रधान मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्योंकि इस बारे मे सारा देश चिंतित है, सदन के अनेक सदस्य कई बार चिंता प्रकट कर चुके है और सारे देश का मामला है इसलिये ऐसी कौन सी वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार उनका है और इसके लिये वह कौन से कदम उठाने जा रहे हैं ?